भोपाल, मंगलमवार
31
मार्च-2026

दैनिक
पीपुल्स प्रवक्ता

भोपाल, ग्वालियर से एक साथ प्रकाशित

/Peoplespravakta

E-paper www.peoplespravakta.com | वर्ष: 09 | अंक : 344 | पृष्ठ : 08 | मूल्य : 02 रूपए | E-mail Peoplespravakta@gmail.com

सुविचार

'बुद्धिमान का उद्देश्य खुशी को सुरक्षित रखना नहीं होता, बल्कि दु:ख को दूर रखना होता है' -अरस्तु

न्यूज ब्रीफ

आंध्र प्रदेश- नेवी कर्मचारी ने प्रेमिका के तीन टुकड़े किए

विशाखापट्टनम, एजेंसी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक शादीशुदा नेवी कर्मचारी ने रविवार 29 मार्च को अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी। फिर उसके शव के कई टुकड़े कर दिए। इसके बाद खुद पुलिस स्टेशन गया और अपना अपराध को कबूल कर लिया। मृतक की पहचान 31 साल की मोनिका के रूप में हुई है। वहीं आरोपी 35 साल का चिंतादा रविंद्र है। शुरुआती जांच के अनुसार, आरोपी ने प्रेमिका का सिर, हाथ और पैर को धड़ से अलग किया। पैरों और कूल्हे के हिस्से को ट्रॉली बैग में छिपा दिया। धड़ को फ्रिज में रखा। सिर और हाथों को सुनसान इलाके में ले जाकर जलाने की कोशिश की। जब पुलिस मौके पर पहुंची, तो घर और फ्रिज में शव के टुकड़े मिले। मोनिका का सिर गायब था। पुलिस को शक है कि रविंद्र ने उसे किसी दूसरी जगह पर ठिकाने लगाया। पुलिस के मुताबिक, आरोपी इंडियन नेवल शिप (ढ्ढहृस्) डेगा में तैनात एक टेक्निशियन है। रविंद्र और मोनिका 2021 में 'मिंगल' नामक डेटिंग ऐप पर मिले थे। इसके बाद दोनों अक्सर विशाखापट्टनम के अलग-अलग स्थानों जैसे पार्क और थिएटर में मिलते थे।

महिला ने बेटियों का सरनेम बदला, पिता ने की शिकायत

वडोदरा, एजेंसी। गुजरात के वडोदरा में एक महिला ने अपनी दोनों बेटियों का सरनेम बदल दिया। बच्चियों के पिता की शिकायत और कोर्ट के आदेश पर पत्नी और वीबग्योर स्कूल के मालिक रुस्तम केरावाला के खिलाफ अटलादरा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। 44 साल के अभिषेक अशोक कुमार मिश्रा ने शिकायत में कहा कि उनकी पत्नी 2019 में दूधसागर डेयरी में नौकरी के लिए मेहसाणा गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि वह वहां पूर्व गृह मंत्री विपुल चौधरी के साथ रहने गई थी। अभिषेक ने दावा किया कि पत्नी के अनैतिक संबंधों से दूधसागर डेयरी में बोनस घोटाला हुआ। यह साजिश तब रची गई जब उनकी पत्नी एचआर डिपार्टमेंट में थी। उन्होंने कहा कि 2019 में इसकी जानकारी गुजरात सरकार को दी थी। मामला गुजरात हाईकोर्ट में चल रहा है।

स्पेन ने अमेरिका के लिए एयरस्पेस बंद किया

वॉशिंगटन डीसी, एजेंसी। स्पेन ने ईरान के खिलाफ युद्ध में शामिल अमेरिकी सैन्य विमानों के लिए अपना एयरस्पेस बंद कर दिया है। साथ ही मिलिट्री बेस के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी है। स्पेन की रक्षा मंत्री मार्गारीटा रोब्लेस ने कहा कि वे अपने एयरस्पेस और सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल ईरान से जुड़े किसी भी सैन्य अभियान के लिए नहीं होने देंगे। इस फैसले के बाद अमेरिकी विमानों को अपना रास्ता बदलना पड़ेगा। हालांकि मानवीय मदद और इमरजेंसी वाली उड़ानों को छूट दी गई है। अर्थव्यवस्था मंत्री कार्लोस कुएर्पो ने भी फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि उनका देश ऐसे युद्ध का साथ नहीं देना चाहते जो बिना वजह शुरू किया गया हो और कानून के खिलाफ हो। प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज पहले ही अमेरिका और इजराइल के सैन्य अभियान की आलोचना कर चुके हैं। वहीं, डोनाल्ड ट्रम्प ने इस फैसले के जवाब में व्यापार से जुड़े कदम उठाने की धमकी दी है।

पंजाब- बरनाला में जैक से उठाई जा रही बिल्डिंग गिरी

बरनाला, एजेंसी। बरनाला में एक मकान गिरने से 3 लोग उसके मलबे में दब गए। इससे तीनों लोगों की मौत हो गई। ये तीनों मकान में अंदर सोए हुए थे। इन्हें मलबे से निकालकर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने इनकी मौत की पुष्टि की। मलबा हटाने के लिए जिला और पुलिस प्रशासन की टीमें पहुंची थीं। उन्होंने जेसीबी मशीनों की मदद से मलबा हटवाया। अधिकारियों ने 3 शव बरामद होने के बाद भी कई घंटे तक जेसीबी चलवाई, ताकि यदि कोई और भी मलबे में दबा हो तो उसे भी निकाला जा सके। बताया जा रहा है कि मकान की नींव धंस जाने के बाद उसे जैक से ऊपर उठाने का काम चल रहा था। जिन लोगों की मौत हुई है, वे इसी काम में लगे हुए थे। ये कुल 4 लोग थे, लेकिन एक व्यक्ति शनिवार शाम को ही घर निकल गया था, जिससे उसकी जान बच गई। जैक से उठाई जा रही थी बिल्डिंग : यह हादसा बरनाला जिले के फरवाही गांव में हुआ।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव को मंत्री काश्यप ने भेंट किया लघु उद्योग निगम के 8 करोड़ रूपए के अंतरिम लाभांश का चैक

एमएसएमई इकाइयां औद्योगिक गतिविधियों का प्रभावी केन्द्र और लाखों परिवारों के स्वावलंबन का हैं आधार

राज्य सरकार प्रदेश के उद्यमियों को प्रोत्साहित करने उपलब्ध करा रही है सहयोग और मार्गदर्शन : सीएम

देश के प्रमुख स्टार्टअप राज्य के रूप में स्थापित हो रहा है प्रदेश

मुख्यमंत्री यादव ने की एमएसएमई इकाइयों को 169 करोड़ से अधिक की राशि अंतरित

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश, देश के सर्वाधिक सशक्त, आर्थिक रूप से सुदृढ़ और बेहतर वित्तीय प्रबंधन वाले प्रथम तीन राज्यों में से एक है। राज्य सरकार प्रदेश के उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए हरसंभव सहयोग और मार्गदर्शन उपलब्ध करा रही है। देश-दुनिया के सभी निवेशकों के लिए प्रदेश के दरवाजे खुले हैं। हम उद्योग मित्र नीतियों और सहयोग की भावना के साथ उनके स्वागत के लिए तत्पर हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में मध्यप्रदेश भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्योग हो या कृषि हर क्षेत्र में योगदान के लिए निरंतर सक्रिय है। एमएसएमई इकाइयां औद्योगिक गतिविधियों का प्रभावी केन्द्र होने के साथ लाखों परिवारों के स्वावलंबन का आधार भी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव सोमवार को समर्थ एमएसएमई विकसित मध्यप्रदेश की थीम पर मुख्यमंत्री निवास में 257 से अधिक एमएसएमई इकाइयों को उनके खाते में 169.57 करोड़ से अधिक की प्रोत्साहन राशि सिंगल क्लिक से जारी कर संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्टार्टअप को लगभग 28 लाख से अधिक की अनुदान राशि की प्रथम किश्त भी जारी की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव को इस अवसर पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कुमार काश्यप ने लघु उद्योग निगम की ओर से 8 करोड़ रूपए के अंतरिम लाभांश का चैक भेंट किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बैतूल और आगर-मालवा के तीन उद्यमियों को औद्योगिक भूमि के लिए आवंटन-पत्र प्रदान किए और मुख्यमत्री उद्यम क्रांति योजना अंतर्गत हितलाभ वितरण भी किए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आज का आयोजन महावीर जयंती के शुभ अवसर पर हो रहा है। यह भगवान महावीर के जनकल्याण और शुचिता के सिद्धांतों को साकार करने का भी प्रतीक है। प्रदेश में उद्योग-व्यापार गतिविधि और उद्यमिता प्रोत्साहित करने के लिए व्यवस्थाओं में पारदर्शिता और गति सुनिश्चित करते हुए निरंतर नवाचार जारी हैं। राज्य सरकार उद्यमियों को लिए पूंजी, भूमि और व्यवस्थाओं में सरलता कर, उनकी प्रगति की राह को आसान बना रही है। विभाग द्वारा बड़ी राशि का सिंगल क्लिक से सीधे अंतरण व्यवस्था में सुगमता और स्पष्टता का परिचायक है। पूरे देश में मार्च क्लोजिंग का वातावरण है, ऐसे में राज्य सरकार द्वारा एमएसएमई इकाइयों और उद्यमियों को राशि और सुविधा उपलब्ध कराई जा रही हैं। यह प्रदेश में नए संकल्पों के साथ नया वित्तीय वर्ष आरंभ करने का भी प्रतीक है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में भी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में ही भारत स्वयं को सुरक्षित महसूस करते हुए प्रगति पथ पर अग्रसर है। युद्ध के दोनों पक्ष भारत का सहयोग कर रहे हैं, यह प्रधानमंत्री मोदी की कुशल नीतियों से ही संभव है। जहां एक ओर विश्व के कई देशों में पेट्रोल-डीजल, गैस की उपलब्धता प्रभावित हो रही है, वहीं हमारे देश में प्रधानमंत्री मोदी ने इनके मूल्यों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ने दिया। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत समर्थ भी है और सक्षम भी।

देश-दुनिया के सभी निवेशकों के लिए खुले हैं प्रदेश के दरवाजे

स्टार्टअप को अनुदान और उद्यमियों को प्रदान किए भू-आवंटन पत्र

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कुमार काश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव जनता के बीच सक्रिय होने के साथ प्रशासनिक दृष्टि से भी निरंतर गतिशील हैं। उनके व्यापक और स्पष्ट दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप प्रदेश उद्योग-व्यापार, कृषि, युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने सहित सभी क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है। प्रमुख सचिव राघवेन्द्र कुमार सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में विभाग में डिजिटल और पारदर्शी व्यवस्थाएं स्थापित की गई हैं। जिसके परिणामस्वरूप भूमि आवंटन प्रक्रिया को गति मिली है। प्रदेश के 25 औद्योगिक क्षेत्रों में विकास कार्य जारी हैं, साथ ही 6 नए औद्योगिक क्षेत्र भी विकसित किए जा रहे हैं। वर्तमान में प्रदेश में 7100 से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश, देश के प्रमुख स्टार्टअप राज्य के रूप में स्थापित हो रहा है। कार्यक्रम में एमएसएमई इकाई के संचालक, उद्यमी और बड़ी संख्या में स्टार्ट-अप्स मौजूद रहे।

अंगोला से एलपीजी खरीदने की तैयारी

इससे खाड़ी देशों पर निर्भरता होगी कम

नई दिल्ली, एजेंसी

ईरान जंग की वजह से भारत में आई गैस की कमी से निपटने के लिए सरकारी तेल और गैस कंपनियां अब नए देशों से रसोई गैस खरीदने का ऑप्शन तलाश रही है। इसी वजह से इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और गेल जैसी कंपनियां अफ्रीकी देश अंगोला की सरकारी कंपनी सोनानगोल से एलपीजी खरीदने पर बातचीत कर रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये कंपनियां सोनानगोल के साथ लंबे समय का समझौता करने पर विचार कर रही हैं। हालांकि, बातचीत अभी शुरुआती दौर में है और सरकार स्तर पर भी चर्चा चल रही है। दरअसल, भारत की 92% एलपीजी खाड़ी देशों से आती है। भारत सरकार इस निर्भरता घटाना चाहती है। ऐसे में अगर अंगोला से करार हो जाता है तो जहाज अटलांटिक और अरब सागर से होते हुए सीधे भारत पहुंचेंगे।

उन्हें होर्मुज स्ट्रेट से नहीं गुजरना होगा। भारत और अंगोला के बीच पहले से तेल और गैस का व्यापार होता रहा है, इसलिए दोनों देशों के बीच भरोसा और सप्लाई सिस्टम पहले से बना हुआ है। इसी वजह से नई डील करना आसान हो जाता है।

रिपोर्ट- अमेरिका की ईरान में घुसकर यूरेनियम जब्त करने की तैयारी

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ईरान के खिलाफ जमीनी कार्रवाई करने का आदेश दे सकते हैं। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रम्प ईरान के पास मौजूद यूरेनियम को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। ईरान के पास करीब 400 किलो समृद्ध (एनरिच्ड) यूरेनियम है, जिसका इस्तेमाल परमाणु बम बनाने में किया जा सकता है। ट्रम्प ने अपने सहयोगियों से कहा है कि ईरान को यह यूरेनियम छोड़ना ही होगा। अगर बातचीत से बात नहीं बनी, तो इसे जबरदस्ती भी लिया जा सकता है। इस बीच, अमेरिका मिडिल ईस्ट में करीब 10,000 अतिरिक्त सैनिक भेजने की योजना बना रहा है। इनमें से 3,500 से ज्यादा सैनिक पहले ही वहां पहुंच चुके हैं। 3500 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक 28 मार्च को मिडिल ईस्ट पहुंचे। इसमें से 2500 मरीन सैनिक थे।

अब जनगणना 2026- पहले चरण के लिए 33 सवाल तय

लिव-इन कपल को शादीशुदा का दर्जा मिलेगा

नई दिल्ली, एजेंसी

जनगणना-2026 का पहला चरण 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है। इसमें 33 सवाल पूछे जाएंगे। इसके मुताबिक, स्थिर रिश्ते में रहने वाले लिव-इन कपल्स को भी शादीशुदा माना जाएगा। ऐसा तब ही होगा जब कपल मानेगा कि उनका रिश्ता लंबा चलने वाला है।

पहले फेज के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया गया है, जहां लोग खुद अपनी जानकारी भर सकेंगे। उनकी मदद के लिए इस पोर्टल पर भी दिए गए हैं।

यह चरण 'हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना' कहलाता है। इसका मकसद देश में घरों और बुनियादी सुविधाओं की जानकारी जुटाना है, ताकि सरकार बेहतर योजनाएं बना सके। दूसरे चरण में आबादी से जुड़ी डिटेल जानकारी ली जाएगी। भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण कहते हैं, 'जनगणना की संदर्भ तिथि (रेफरेंस डेट) बहुत महत्वपूर्ण है। संदर्भ समय 1 मार्च की आधी रात है, जो 28 फरवरी 2027 और 1 मार्च 2027 के बीच पड़ती है। इस संदर्भ तिथि का उल्लेख 16 जून 2025 को जारी पहली अधिसूचना में किया गया था, जिसमें जनगणना कराने के इरादे की घोषणा की गई थी। इसी संदर्भ तिथि के कारण इसे जनगणना 2027 कहा जाता है।

नवीन पटनायक बोले- निशिकांत दुबे को मेंटल डॉक्टर की जरूरत

नई दिल्ली।

ओडिशा के पूर्व ष्टरूऔर बीजू जनता दल चीफ नवीन पटनायक ने सोमवार को पिता बीजू पटनायक पर टिप्पणी को लेकर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की आलोचना की। भुवनेश्वर में मीडिया से बातचीत में पटनायक ने कहा- बीजेपी सांसद का बयान आपत्तिजनक है और उन्हें मेंटल डॉक्टर की जरूरत है। नवीन पटनायक ने कहा- मैं उस समय करीब 13 साल का था और मुझे याद है कि चीनी हमले को लेकर बिजू बाबू कितने गुस्से में थे। उन्होंने उसे रोकने के लिए क्या-क्या किया। दरअसल, 27 मार्च को निशिकांत ने दावा किया था कि 1962 में चीन से युद्ध के दौरान बीजू पटनायक, तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू, अमेरिका और सीआईए (सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी) के बीच कड़ी थे। बीजद ने सोमवार को निशिकांत दुबे की टिप्पणी के विरोध में राज्यसभा से वॉकआउट किया। कार्यवाही शुरू होते ही सस्मित पात्रा ने कहा- निशिकांत दुबे ने बीजू पटनायक को सीआईए एजेंट बताया है।

शाह बोले- जो हथियार उठाएगा, उसे कीमत चुकानी होगी

वामपंथियों ने भोले-भाले आदिवासियों को अंधेरे में रखा, अब बस्तर से लाल आतंक लगभग खत्म

पीपुल्स प्रवक्ता, नई दिल्ली।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में 'नक्सल मुक्त भारत' मुद्दे पर चर्चा के दौरान सरकार की तरफ से जवाब दे रहे हैं। उन्होंने कहा- जो लोग पूरी व्यवस्था को नकार कर हथियार उठा लेते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। हथियार उठाने वालों को उसकी कीमत चुकानी होगी। शाह ने कहा- सालों से भोले-भाले आदिवासियों को अंधेरे में रखा गया। वामपंथियों ने अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए भोले भाले आदिवासियों को बहकाया। कांग्रेस ने आजादी के बाद 75 साल में 60 साल राज किया। फिर आदिवासी विकास से क्यों बच गए। शाह ने कहा- कांग्रेस ने 60 साल के दौरान आदिवासियों तक घर, स्कूल, मोबाइल टॉवर नहीं पहुंचने दिया और अब हिसाब मांग रहे हैं। अपने गिरेबान में झांककर देखिए। जो लोग नक्सलवाद की वकालात करते हैं, उनसे पूछना चाहता हूं ये सब 1970 से अब तक क्यों नहीं हुआ था। संसद में आज नक्सलवाद पर चर्चा सरकार की तरफ से दी गई डेडलाइन खत्म होने से एक दिन पहले हो रही है। शाह कई बार 31 मार्च, 2026 तक देश से नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म करने की घोषणा कर चुके हैं। शाह ने कहा- ये जो बड़ी घटना देश में आकार लेने जा रही है उसका श्रेय सीएपीएफ खासकर कोबरा, सीआरपीएफ के जवान और छत्तीसगढ़ पुलिस और वहां के स्थानीय आदिवासी बाशिंदों को जाता है। यहां पर वामपंथी उग्रवाद समाप्त होने जा रहा है। इसमें वहां की जनता का भी बहुत बड़ा हाथ है। जो हजारों युवा मारे गए, जो जवान शहीद हो गए उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। गृह मंत्री ने कहा- नक्सलियों की विचारधारा का विकास से कोई लेना-देना नहीं है। जब हम आजाद हुए हमने कहा 'सत्यमेव जयते'। सत्य की हमेशा विजय हो। इनका ध्रुव वाक्य है- सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। यहां सत्ता शब्द का संबंध अपनी विचारधारा की विजय के लिए है। विचारधारा को आदिवासियों में फैलाकर सत्ता हासिल करने के लिए है। यहां विकास की कोई बात नहीं है।

नक्सलवाद का मूल कारण विकास नहीं, एक विचारधारा है

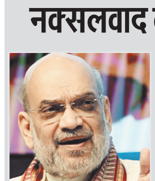

शाह ने कहा- सरकार ने ढेर सारी योजनाएं बनाई लेकिन आपने (कांग्रेस) उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं करने दिया। 12 राज्यों में रेड कॉरिडोर था। वहां कानून का शासन नहीं था। 12 करोड़ लोग गरीबी में जी रहे थे। किसी ने चिंता नहीं की। हजारों युवाओं की मौत हुई। एक एनजीओ के मुताबिक, 20 हजार युवा मारे गए। लोग दिव्यांग हो गए। उन तक विकास नहीं पहुंचा।

गृह मंत्री ने कहा- 2014 में बदलाव हुआ। धारा 370 हटी, 35ए हटा, राम मंदिर बना, सीएए का कानून आ गया है, विधायी मंडलों में महिलाओं को 33% आरक्षण मिल गया है। ये सारे काम नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल में हुए। शाह ने कहा- पिछले 12 साल में देश को गरीबी से मुक्ति दिलाने के लिए, युवाओं के लिए नई शिक्षा पद्धति लाने के लिए, आंतरिक-बाहरी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, देश के मूल्यों से न जुड़ी हुई पॉलिसी को दरकिनार करने के लिए बहुत कुछ हुआ। गृह मंत्री ने कहा- अगर कोई पॉलिटिकल साइंस का छात्र इसकी रेटिंग करेगा कि सारी चीजों से सबसे ज्यादा फायदा किस फैसले से हुआ है तो वो छात्र नक्सलमुक्त भारत को पहले नंबर पर रखेगा। शाह ने कहा- इन सबके लिए कौन जिम्मेदार है। नक्सलवाद का मूल कारण विकास की डिमांड नहीं, एक विचारधारा है। राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के लिए 1970 से इंदिरा गांधी ने स्वीकार कर लिया कि वामपंथी विचारधारा के कारण नक्सलवाद फैला। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने स्वीकारा था कि जम्मू-कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट की तुलना में देश की आंतरिक सुरक्षा में सबसे बड़ी समस्या माओवादी है।

लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा आतंकी अहमद हुआ अरेस्ट

दिल्ली, तमिलनाडु में तैयार कर रहा था आतंकी मॉड्यूल

नई दिल्ली, एजेंसी

दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियों ने सोमवार को लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकी शब्बीर अहमद लोन को दिल्ली बॉर्डर से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जांच में सामने आया है कि वह बांग्लादेश से भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। पुलिस के मुताबिक, शब्बीर दिल्ली, कोलकाता और तमिलनाडु में आतंकी गतिविधियों के लिए युवाओं की भर्ती करने की तैयारी में था।

यह पूरा नेटवर्क पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर ऑपरेट हो रहा था। साल 2007 में भी दिल्ली पुलिस ने आतंकवाद के आरोपों में लोन को गिरफ्तार किया था। 2019 में जमानत मिलने के बाद वह बांग्लादेश भाग गया था। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने 26 मार्च को शब्बीर के आतंकी मॉड्यूल की जांच के लिए कश्मीर के तीन जिलों, गांदरबल, शोपियां और श्रीनगर के 10 ठिकानों पर रेड मारी थी। इस मामले के तार एक ट्रांजैक्शनल नेटवर्क से जुड़े पाए गए हैं, जिसमें मॉड्यूल को बांग्लादेश और पाकिस्तान में बैठे लश्कर-ए-तैयबा के हैंडलर्स से निर्देश मिल रहे थे।